भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3644
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी करना

3644. श्री बैन्नी बेहननः
श्री जिया उर रहमानः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कोई नीतियां बनाई हैं;
(ख) यदि हां, तो अपनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वायदा किया था, देश में किसानों को अपनी आय कब तक दोगुनी होने की आशा है; और
(घ) सरकार द्वारा भंडारण सुविधाओं जैसी आवश्यक कृषि अवसंरचना के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि 22 प्रतिशत की अनुमानित खाद्यान्न बर्बादी को रोका जा सके?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास के लिए उचित उपाय करती हैं। हालाँकि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। किसानों की आय बढ़ाने की कार्यनीतियों में फसल उत्पादकता में सुधार, उत्पादन की लागत में कमी, कृषि विविधीकरण, सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन और किसानों के नुकसान की भरपाई करना शामिल है।

विभिन्न सुधार और नीतियां, इनपुट के उपयोग को आधुनिक और तर्कसंगत बनाकर किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने, लाभकारी रिटर्न, आय सहायता, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 में 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 122528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची **अनुबंध** पर दी गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ा ली है।

(घ): मौजूदा इनफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने और एग्री इनफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जुटाने और एग्री इनफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को बदलने के लिए एग्री इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) आरंभ किया गया था। ए.आई.एफ. ब्याज छूट और ऋण गारंटी समर्थन के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इनफ्रास्ट्रक्चर और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (यूनियन कैबिनेट) ने पात्र परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करके दिनांक 28.8.2024 को ए.आई.एफ. के प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी। इसमें सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं और पीएम कुसुम 'ए' के अभिसरण के तहत कवर किए गए इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए व्यक्तिगत पात्र लाभार्थियों को अनुमति देना शामिल है। ए.आई.एफ. के तहत अनुमोदित प्रमुख परियोजनाओं में 18,606 कस्टम हायरिंग सेंटर, 16,276 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 13,724 गोदाम, 3,102 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयां, 1,909 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं और लगभग 21,394 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां हैं।

अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
5. एग्री इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
8. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
9. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
12. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
13. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
15. डिजिटल कृषि मिशन
16. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) - राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम-ई नाम)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) - अन्य (आईएसएएम-अन्य)
18. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
19. सॉइल हेल्थ कार्ड (एसएचसी)
20. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
21. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
22. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
23. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
24. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
25. कृषि वानिकी
26. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
27. राष्ट्रीय बांस मिशन

*****